भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3682
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शिकायतें

3682. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, घटिया सामग्री के उपयोग या उनकी पूर्णता की गलत सूचना दिए जाने के बारे में लोक शिकायत पोर्टलों या राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है:

(ख) कितनी शिकायतों की जाँच और समाधान किया गया तथा कितनी शिकायतें अभी भी लंबित हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में और विशेषकर जौनपुर जिले में, अपनी मूल समय-सीमा से अधिक विलंबित हो चुकी सड़क विकास और उन्नयन परियोजनाओं की सूची क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में भ्रष्टाचार, खराब सामग्री के उपयोग, या सड़क परियोजनाओं की पूर्णता की गलत स्थिति की सूचना देने से संबंधित कोई विशेष शिकायत लोक शिकायत पोर्टलों, जैसे कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। राज्य ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल 3,223 सामान्य शिकायतें लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज की गईं हैं - जो मुख्यतः नई सड़क के निर्माण की माँगों से संबंधित हैं। इन सभी शिकायतों की विधिवत जाँच और निपटान किया गया है।

इसके अलावा, "मेरी सड़क" मोबाइल ऐप जो पीएमजीएसवाई के तहत एक विशिष्ट नागरिक प्रतिक्रिया मंच के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से कुल 7,031 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह मंच उपयोगकर्ताओं को कार्यों की धीमी प्रगति, छोड़ी गई परियोजनाओं और सड़कों या पुलों की खराब गुणवत्ता जैसे मुद्दों की सूचना देने में सक्षम बनाता है, जो अक्सर भू-टैग की गई फोटो के साथ समर्थित होते हैं। इनमें से 2865 शिकायतें खराब गुणवत्ता से संबंधित हैं, 1763 सड़क चयन या संरेखण से संबंधित हैं, 850 छोड़े गए कार्यों के संबंध में हैं, 630 निर्माण की धीमी गति के संबंध में हैं और 521 भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दे आदि के संबंध में हैं। इन शिकायतों को समाधान के लिए राज्य को भेज दिया गया था। "मेरी सड़क" ऐप के माध्यम से प्राप्त, 3

शिकायतों को छोड़कर, जिनके समाधान वर्तमान में लंबित हैं, सभी शिकायतों के लिए अंतिम प्रतिक्रियाएं प्रदान कर दी गई हैं।

(ग) शुरूआत से अब तक (07.08.2025), उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न इंटेरवेंशनों/घटकों के अंतर्गत 77,425 किलोमीटर लंबाई के साथ कुल 21,125 सड़कें और 18 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 75,348 किलोमीटर लंबाई के साथ 20,946 सड़कें और 17 पुल पूरे हो चुके हैं।

जौनपुर जिले में 1,194 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 341 सड़कों को मंजूरी दी गई है और सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

इसके अलावा, राज्य में पीएमजीएसवाई-I और पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत सभी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के जारी कार्यों और पीएमजीएसवाई-III को पूरा करने की समय-सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, परियोजनाओं के पूरा होने में लगने वाले समय के कारण लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि का वहन केन्द्र सरकार नहीं करती है।

***